‘माईगव’ की ई-प्रशासन में भूमिका

उमेश कुमार

Ikjk'k% *नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नीतिनिर्माण और उसके कार्यान्वयन में अपने विचार व्यक्त करने की उत्सुकता ने एक समर्पित सोशल मीडिया मंच की अवधारणा को जन्म दिया है। माईगव उसी अवधारणा का परिणाम है जो नागरिकों को उनकी रूचि, और समय की उपलब्धता के अनुसार समान भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इस मंच पर नागरिकों को डिस्कस (चर्चा करने), डू (कार्य करने), और डिसेमिनेट् (प्रसार) 3डी माध्यम से विचारों, सुझावों और जमीनी स्तर पर उनके योगदान के द्वारा उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ई -शासन तार्किक रूप से ''नागरिक जुड़ाव'' में निहित है। शासन की प्रक्रियाओं को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। 'माईगव' ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 15 राज्यों में राज्य संस्करण भी लांच किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में 'माईगव' (मेरी सरकार) की ई-शासन में भूमिका का वर्णन किया गया है। साथ ही उन पहलुओं को भी उल्लेखित किया गया है जो माईगव को और उपयोगी एवं समावेशी बना सकता है इसी सन्दर्भ में यह सुझाव दिया गया है की 'माईगव' को बिहार राज्य संस्करण भी लांच करना चाहिए। यह बिहार राज्य में जनता को ई-शासन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।*

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र, जैसा की संविधान में निहित है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है जो की जनता के प्रति जवाबदेह होती है। हालांकि आजादी के समय से ही सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन विशाल आबादी, विविध संस्कृति, भाषा,

धर्म, समुदाय और जाति होने के कारण लोकनीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन में बाधाएं हो रही हैं।

ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए लोकनीति के निर्माण एवं प्रशासन में जनता की भागीदारी जरूरी है और ई-शासन के द्वारा जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है। इसका उदेश्य नागरिकों की सूचना तक पहुँच और उसके उपयोग के माध्यम से सशक्त बनाना है। ई-शासन का अर्थ किसी संगठन चाहे वह निजी अधिकरण हो या नागरिक समाज संगठन (सरकार को छोड़कर) को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और संचालन में सहायता के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। दूसरे शब्दों में, ई-शासन का संबंध लोककल्याण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग करने से है। ई-गवर्नेंस नीति-निर्माताओं और नागरिकों के बीच एक दो-तरफा सड़क बनाता है जो प्रक्रिया-केंद्रितता से नागरिक केंद्रितता में बदलाव को सक्षम बनाता है।

ई-गवर्नेंस में जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सोशल मीडिया प्लेटफार्म की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 26 जुलाई 2014 को 'माईगव' (MyGov) को भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जी द्वारा किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बंटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना है। 'माईगव' नागरिकों को अनेक विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श में भाग लेने का अवसर देता है तथा अनेक लोगों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का मौका देता है। नागरिक इस मंच पर कागजात, केस स्टडी, चित्र, वीडियो और अन्य कार्य योजनाएं अपलोड कर सकते हैं। वे ऐच्छिक रूप से विविध कार्य कर सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं। विशेषज्ञ और अन्य सदस्य इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। अनुमोदित होने पर इन कार्यों की जानकारी उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने कार्य पूरा किया है तथा माईगव के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र-एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस पोर्टल का प्रबंधन करेंगे। जो लोग विचार-विमर्श से आगे बढ़कर जमीनी योगदान देना चाहते हैं उनके लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल अनेक अवसर देता है। माईगव ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे 15 राज्यों में राज्य संस्करण भी लांच किया है।

माईगव की ई-प्रशासन में भूमिका

ekb'x0 ¼MyGov½ सहभागी शासन और तकनीकी कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसका उदेश्य लोगों की भागीदारी के जरिए गुणात्मक परिवर्तन लाना है। जन सहभागिता के मामले में माईगव को महत्वपूर्ण सफलता मिली भी है। प्रमुख

राष्ट्रीय परियोजनाओं के लोगो और टैगलाइन को माईगव के माध्यम से क्राउडसोर्स किया गया है। स्वच्छ भारत के लिए लोगो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए लोगो, डिजिटल इंडिया अभियान के लिए लोगो आदि क्राउडसोर्स से जुड़ी कुछ उल्लेखनीय पहल हैं। माईगव ने समय-समय पर नागरिकों से नीतियों के ड्राफ्ट पर इनपुट भी मांगे हैं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डेटा सेंटर नीति, डेटा संरक्षण नीति, राष्ट्रीय बंदरगाह नीति, आईआईएम विधेयक आदि प्रमुख हैं। माईगव अक्सर मन की बात, वार्षिक बजट, परीक्षा पे चर्चा और ऐसी कई अन्य पहलों के लिए आइडिया आमंत्रित करता रहता है। भारत सरकार का उद्देष्य नागरिकों के विचारों, सुझावों और जमीनी स्तर पर योगदान के द्वारा उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है इसके लिए तीन माध्यम चुने गए हैंः–'चर्चा' (डिस्कस), 'करना'(डू) और 'प्रसार' (डिसेमिनेट)। निम्नलिखित रूप मे इसकी विस्तार से चर्चा की गयी हैः–

डिस्कस (चर्चा करना):– चर्चा अनुभाग नागरिकों को उनकी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सरकार के नीतिगत पहल में सुधार के लिए विषय-आधारित चर्चाओं पर विचार व्यक्त करने में मदद करता है। नागरिक विभिन्न राष्ट्रीय विषयों पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं साथ ही साथ दूसरे नागरिकों के विचार पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इन चर्चाओं से सरकार के विभिन्न मंत्रालय नीतिगत विषयों में जमीनी रूप से बन रही राय को शामिल कर सकतें हैं। जैसे कि रेल बजट (2015-2016, 2016-17) में नागरिकों के सुझावों को शामिल करना और उनका कार्यान्वयन डिस्कस पोर्टल की सफल परिणति दर्शाता है।

डू (कार्य करना):– इस अनुभाग में नागरिक अपनी रूचि के अनुसार 'ऑनलाइन टास्क' और ऑन-ग्राउंड टास्क' पर कार्य कर सकते हैं। इस अनुभाग में विभिन्न प्रकार के कार्य लगातार चलते रहते हैं जो नागरिकों को सरकार के विभिन्न लोकनीति के कार्यान्वयन में जुड़ने के लिए प्रेरित करतें हैं। 80 समूहों में प्रत्येक माइगव प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। जैसे जल संरक्षण पर कविता लिखने की प्रतियोगिता, वेबसाइट अवलोकन खंड ब्रांड नाम प्रतियोगिता, लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, लघु फिल्म प्रतियोगिता, प्रधानमंत्री की विभिन्न वार्ताओं के लिए प्रश्नों को साझा करना जैसे परीक्षा पर चर्चा, युवा संसद, नई शिक्षा नीति के लिए प्रतीक-चिन्ह बनाएं आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं या तो संबंधित विभाग/मंत्रालय के समूह पर आयोजित किया जाता है या इसे माईगव के रचनात्मक कोर्नर के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय नागरिकों के लिए एक लघु एनिमेशन फिल्म प्रतियोगिता खुली है। प्रविष्टियां केवल 2डी/3डी एनिमेटेड लघु फिल्मों के लिए खुली हैं, जिनमें से प्रत्येक की अवधि अधिकतम तीन मिनट है। प्रतियोगिता का विषय भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष है। एनिमेटेड लघु फिल्में हिंदी/अंग्रेजी में प्रतिलेख (शब्दशः) के साथ 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी एक में बनाई जा

सकती है। इसी प्रकार संस्कृति मंत्रालय सभी क्षेत्रों के नागरिकों को युवा महोत्सव के लिए एक लोगों डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। लोगो को युवा महोत्सव मनाने की भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। (https://www.mygov.in/home/77254/do/)।

माईगव पर ऑनलाइन पोल और सर्वेक्षण भी होते हैं जो नागरिक को विशेष नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय रखने का अवसर प्रदान करता है। ऑनलाइन पोल और सर्वेक्षण से सरकार को सरकारी नीतिगत पहलों की जनता के बीच प्रभावशीलता का भी पता है। कई सरकारों ने स्मार्ट सिटी (जैसे बिहार शरीफ, नया रायपुर और क्षेत्र आधारित विकास के लिए गाजियाबाद और चंडीगढ़) मिशन के लिए रीट्रोफिटिंग क्षेत्र की पहचान के लिए माईगव पर पोल करवाया है। इसी प्रकार अपने नगर में शहरी ''चुनौतियों की पहचान करने में सहयोग दें'' सर्वेक्षण का उद्देश्य नगरों में नागरिकों के समक्ष आने वाली प्रमुख शहरी चुनौतियों को समझना है। इस प्रकार माईगव नागरिकों को उनकी रूचि, विशेषज्ञता और समय की उपलब्धता के अनुसार लोकनीति के निर्माण एवं कार्यन्वयन मे भागीदारी को सुगम बनाता है।

डिसेमिनेट् (प्रसार करना): वर्गीकृत सूचनाओं को ब्लॉग, वार्ता, न्यूजलेटर्स के माध्यम प्रसारित किया जा रहा है। वार्ता को माईगव पर निर्णय निर्माताओं के साथ संवाद के रूप मे परिभाषित किया गया है। यह नागरिकों को लाइव चैट के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधि जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। यह सुविधा वास्तविक समय विचार और राय को आदान-प्रदान करने का अवसर देती है साथ ही साथ यह सरकारी एजेंसियों और नागरिकों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, आदि को नागरिकों के साथ लाइव वीडियो बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।

माईगव ब्लॉग सरकारी पहल और गतिविधियों की अपडेट, अनुभव और माईगव इंपैक्ट प्रदान करता है जो नागरिकों को अद्यतित रहने में मदद करता हैं। ब्लॉगों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम, नीति निर्माण आदि का भी प्रचार-प्रसार किया जाता है। माईगव साप्ताहिक, पाक्षिक प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम संबंधित समाचारों और सूचनाओं का प्रसार भी करता है। ये समाचार पत्र अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होते हैं।

माईगव ने माईगॉव माइक्रो-साइट्स की मदद से भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यकर्मों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है, 'स्वच्छ भारत अभियान', 'बदलते भारत', 'मेरी सरकार' इनोवेशन' और 'ई-ग्रीटिंग्स' कुछ प्रमुख माइक्रो-साइट्स हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य माइगव की ई-शासन में भूमिका का पता करना है। मोटे तौर पर अध्ययन की प्रकृति खोजपूर्ण है और डेटा एकत्र करने की तकनीकों में

वेबसाइट अवलोकन और द्वितीयक डेटा जैसे कि सरकारी रिपोर्ट और अकादमिक प्रकाशन के संदर्भ पर निर्भर करता है।

बिहार में माईगव की आवश्यकता एवं सम्बंधित सुझाव

जिस प्रकार माईगव केन्द्रीय स्तर पर तथा अन्य राज्यों मे विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत् है उसी प्रकार आवश्यकता है की इस ICT के दौर मे माईगव बिहार जैसे पोर्टल को अपनाया जाए तथा विकास को गतिशीलता प्रदान की जा सके।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैंः–

- इसके द्वारा बिहार में चल रहे विभिन्न योजनाओं को एक प्लेटफार्म पर लाकर नागरिकों को सभी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।
- इस प्लेटफार्म की सहायता से बिहार की जनता को जननीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भागीदारी के लिए उन्मुख किया जा सकता है।
- इस प्लेटफार्म का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने के साथ तकनीकी क्षमता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं का लाभ जनता तक त्वरित रूप से पहुँचाया जा सकता है और लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

माईगव ने अतीत में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों के निर्माण के आधार के रूप में लोकप्रिय नागरिक राय का सफलतापूर्वक योगदान दिया है। ''नई शिक्षा नीति'' में योगदान देने से लेकर रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों के लिए विचारों को क्राउडसोर्सिंग करने तक, माईगव ने आधुनिक समय में एक बुनियादी 'ई-सरकार' को एक व्यापक, समग्र और सुचारू ई-गवर्नेंस में परिवर्तित करके अपनी प्रासंगिकता साबित की है। सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने के लिए कई डिजिटल पहलें की गई हैं लेकिन वे मुख्य रूप से केवल सेवा वितरण घटक तक ही सीमित थीं। हालाँकि, माईगव जैसे मंच की स्थापना के साथ, विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के प्रशासक नीति निर्माण से पहले 'जनता की आवाज' पर विचार करने में सक्षम हैं। शासन की प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी का आह्वान करने के लिए एक स्वदेशी सोशल मीडिया की आवश्यकता स्थापित होने के बाद, यह अपनी रणनीतियों को विकसित करने के लिए जमीन तैयार करता है ताकि यह भविष्य में प्रत्याशित सभी अप्रत्याशित परिवर्तनों का सामना कर सके।

संदर्भ

1. Santap Sanhari Mishra (2020) Testing the antecedents to e&democracy towards citizens* happiness: a structural equation modelling approach to 'MyGov' initiative, India, International Journal of Public Administration, 43:15, 1293-1303, DOI: 10.1080/01900692.2019.1669051
2. http://yojana.gov.in/hindi/topstory_detailsjune16-1.asp
3. eksfgr Hkêkpk;Z] yksd ç'kklu ds u;s vk;ke] 2014 i'-&484
4. https://www.mygov.in/[9]
5. https://www.mygov.in/hi/simple-pag
6. https://www.mygov.in/
7. https://www.mygov.in/home/do/
8. https://www.mygov.in/hi/home.talk
9. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2888451.2888463
10. Malhotra, Charru and Sharma, Abhinav and Agarwal, Nishtha and Malhotra, Ishita, 2019, Review of Digital Citizen Engagement (DCE) Platform: A Case Study of MyGov of Government of India, 2019.
11. Cooper, T.L., 2005, Civic engagement in the twenty-first century: Toward a "scholarly and practical agenda. Public Administration Review.
12. Angela Susan Mathew, Transition From E&Participation To Engagement on Governmentinitiated Digital Platforms: A Qualitative Study of Mygov-in
13. Tech, I.T. (2020). WhatsApp and MyGov launch official coronavirus and Covid-19 alert service for India, here is how you can use it.
14. COVID, I. 19 [Internet]. MyGov. in. 2020 [cited 2020 May 26].